चीनी पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी में फूड मिनिस्ट्री

[पीटीआई *नई दिल्ली*]

सरकार देश में चीनी के इम्पोर्ट पर ड्यूटी बढ़ाकर 20 फीसदी करने पर विचार कर रही है। इसका मकसद देश में इम्पोर्टेड चीनी की मात्रा पर नियंत्रण रखना है।

फूड मिनिस्टर के वी थॉमस ने बताया कि सरकार कच्ची चीनी पर इम्पोर्टेड ड्यूटी खत्म करने के बारे में भी सोच रही है। इस समय सफेद और कच्ची चीनी दोनों पर इम्पोर्ट ड्यूटी 10 फीसदी है। थॉमस ने कहा, 'हमारे सामने कई प्रपोजल हैं। एक सफेद चीनी पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 20 फीसदी करने का है। दूसरा कच्ची चीनी पर ड्यूटी घटाकर शून्य करने से जुड़ा है।'

सरकार कच्ची चीनी पर इम्पोर्टेड ड्यूटी हटाना चाह रही है। इस समय सफेद और कच्ची चीनी दोनों पर इम्पोर्ट ड्यूटी 10 फीसदी है

इस बारे में जल्द ही फैसला किया जाएगा। थॉमस ने बताया कि संबंधित मिनिस्ट्रीज से विचार-विमर्श करने के बाद अगले 10-15 दिनों में एक कैबिनेट नोट पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कच्ची चीनी पर इम्पोर्ट ड्यूटी हटानी जरूरी है। इससे देश में इम्पोर्टेड चीनी को रिफाइंड किया जाएगा, जिससे देश में रोजगार बढ़ाने में मदद मिलेगी। चीनी के निर्यात पर थॉमस का कहना था कि 2012-13 के लिए इस महीने शुरू हुई फ्री शुगर एक्सपोर्ट पॉलिसी जारी रहेगी। इस साल मई में चीनी का एक्सपोर्ट ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के तहत सिर्फ सितंबर तक के लिए खोला गया था। हालांकि, अब इसे आगे के लिए भी बढ़ा दिया गया है। इस साल देश में चीनी का उत्पादन 2.6 करोड़ टन रहने का अनुमान है।

वहीं, इस दौरान शुगर की डिमांड 2.2 करोड़ टन रहने की ही उम्मीद है। इसका मतलब यह है कि देश के पास एक्सपोर्ट करने के लिए सरप्लस चीनी मौजूद होगी। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने फ्री शुगर एक्सपोर्ट पॉलिसी को जारी रखने की बात कही है।

Economic Times

19/10/12